दक्षिण एशिया में अपने स्वार्थ साधने की कोशिश में

आतंकवाद की पैरोकारी करता चीन

चीन ने एक फिर जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित होने से बचाकर अपनी प्राथमिकता दुनिया को बता दी है. चीन भारत से खरबों रुपये कमाता है और दूसरी तरफ आनेवाले दशकों में विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने का सपना देखता है. अपनी महत्वाकांक्षा में अंधा होकर चीन आतंकियों को पनाह देनेवाले पाकिस्तान की हर संभव मदद कर रहा है और उसके गुनाहों पर बार-बार पर्दा डाल रहा है. इन बातों से भड़ककर भारत में एक बार फिर चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग उठी है और व्यापारिक संबंध तोड़ने की बात भी चल रही है. इन्हीं बहसों के आलोक में प्रस्तुत है आज का **इन दिनों**...

भारत-चीन व्यापार आंकड़ा

वर्ष 2017-18 में भारत ने चीन को कुल 303,526.16 मिलियन डॉलर मूल्य के वस्तुओं का निर्यात किया था, जबकि 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर तक) में यह निर्यात 243,963.15 मिलियन डॉलर का रहा. वहीं वर्ष 2017-18 में भारत ने चीन से 465,580.99 मिलियन डॉलर व 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर तक) में 389,927.47 मिलियन डॉलर मूल्य के वस्तुओं का आयात किया था.

भारत द्वारा चीन किया जानेवाला निर्यात

(मूल्य : मिलियन डॉलर में)

वस्तुएं	2017-18	2018-19 (अप्रैल-दिसंबर तक)
कार्बनिक रसायन	2,106.24	2,409.27
तांबा व इससे बनी सामग्री	1,548.47	176.27
खनिज ईंधन, खनिज तेल व अन्य	1,507.21	2,525.38
अयस्क, लावा व राख	1,259.79	890.52
कपास	1,003.28	1,231.41

चीन से भारत में होनेवाला आयात

(मूल्य : मिलियन डॉलर में)

वस्तुएं	2017-18	2018-19 (अप्रैल-दिसंबर तक)
इलेक्ट्रिकल मशीनरी, उपकरण, कल-पुर्जे, साउंड रिकॉर्डर व अन्य	28,672.44	16,075.87
न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी व अन्य	13,539.97	9,898.81
कार्बनिक रसायन	7,091.53	6,605.40
प्लास्टिक व इससे बने सामान	2,365.49	2,033.51
लौह व इस्पात	1,621.03	1,097.31

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

व्यापार अवरुद्ध कर चीन को दिया जाये जवाब

डॉ अश्विनी महाजन
एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली विवि

भारत को चीन से 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (एमएफएन) का दर्जा वापस ले लेना चाहिए, जैसा पाकिस्तान के साथ किया गया था. सुरक्षा की दृष्टि से चीन के रक्षा और टेलीकॉम उपकरणों पर भी सामरिक कारणों से प्रतिबंध लगाये जायें, क्योंकि इन साजो-सामान के आयात से हमारी सुरक्षा खतरे में है.

भारत ही नहीं पूरा विश्व जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है. दुनियाभर में किसी को भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आज आतंकवादियों की पनाहगाह बना हुआ है. अमेरिका भी जानता है कि अमेरिका पर हुए भीषण आतंकवादी हमले के मुख्य गुनहगार ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने पनाह दे रखी थी. आज मसूद अजहर, जो दुर्दांत आतंकवादियों का सरगना है, वह भी लगातार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है. पाकिस्तान की सरकार तो जैसे आतंवादियों की बंधक बनी हुई है. लेकिन, चीन जब पाकिस्तान के अंध-समर्थन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकवादी को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर लगातार चौथी बार अड़ंगा लगाता है, तो भारत समेत दुनियाभर के देशों में गुस्सा आना स्वाभाविक ही है. आज सुरक्षा परिषद् के 13 सदस्य इस प्रस्ताव पर एकजुट हैं, लेकिन चीन के वीटो के कारण मसूद अजहर आज तक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं हो सका है.

आतंकवाद से जूझते हुए अमेरिका और यूरोप के देश चीन के इस प्रस्ताव से अत्यंत खिन्न हैं और अमेरिका ने तो यहां तक कहा है कि चीन के वीटो के बाद अब उन्हें इस लड़ाई में अन्य रास्ते खोजने होंगे. चीन का यह कदम काफी चिंतनीय है, जिसकी हर स्तर पर आलोचना हो रही है. उसका यह कदम दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अड़चन है. मौका है कि चीन के खिलाफ कूटनीतिक से लेकर आर्थिक कदम तक उठाये जायें, ताकि उसे पता चल सके कि ऐसी गैर-जिम्मेदाराना करतूत का खामियाजा कितना गंभीर होता है. साफ है कि चीन को अपने इस कुकृत्य की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

यह सर्वविदित है कि चीन की अर्थव्यवस्था निर्यातों पर निर्भर करती है. पिछले काफी समय से दुनिया में भारी सब्सिडी होने का फायदा उठाकर चीन ने वैश्विक बाजारों पर कब्जा जमा लिया है. इसके फलस्वरूप दुनियाभर में मैन्युफैक्चरिंग को भारी नुकसान हुआ और उसका प्रभाव भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर भी पड़ा. अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और बाकी तमाम मुल्कों में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण चीन ही है.

दुनियाभर में अधिकतर देश चीन से इस कारण से नाराज भी हैं. पिछले कुछ समय से अमेरिका ने चीन से आनेवाले साजो-सामान पर आयात शुल्क बढ़ा दिये हैं, जिसके कारण चीन के निर्यातों पर भारी प्रभाव पड़ रहा है. गौरतलब है कि अमेरिका चीनी सामानों का सबसे बड़ा बाजार है और अमेरिका को चीन से 419 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है. भारत भी चीन के सामान का एक बड़ा बाजार है और चीन हमें लगभग 76 अरब डॉलर का सामान निर्यात करता है और चीन से हमारा व्यापार घाटा 63 अरब डॉलर है.

चीन न केवल दुनिया के लिए आर्थिक खतरा है, बल्कि चीन अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी खतरा बना हुआ है. चीन के अपने लगभग सभी देशों के साथ सीमा विवाद हैं, क्योंकि चीन उन देशों की भूमि पर अपना अधिकार जताता रहता है.

आज दुनियाभर में चीन के खिलाफ माहौल है और उसे सबक सिखाने के लिए इससे अच्छा मौका दुनिया को नहीं मिलेगा. भारत को चीन से 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (एमएफएन) का दर्जा वापस ले लेना चाहिए, जैसा पाकिस्तान के साथ किया गया था. सुरक्षा की दृष्टि से चीन के रक्षा और टेलीकॉम उपकरणों पर भी सामरिक कारणों से प्रतिबंध लगाये जायें, क्योंकि इन साजो-सामान के आयात से हमारी सुरक्षा खतरे में है. पूर्व में की गयी ऐसी कार्रवाई से चीनी सामानों के आयात पर असर देखा गया है, लेकिन प्रतिबंधों को और कड़ा करने की जरूरत है. गौरतलब है कि साल 2018 के बजट में जो चीनी सामान पर आयात शुल्क बढ़ाये गये, उससे छह महीने में ही चीनी आयात 2.5 अरब डॉलर कम हो गया था.

गौरतलब है कि डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुसार जो आयात शुल्क लगाया जा सकता है, उससे भी कम शुल्क चीनी सामानों पर लगाया जाता है. इसलिए चीनी आयात को कम करने के लिए भारत सरकार को कड़ी कार्रवाई करते हुए उसके सामानों पर शुल्क बढ़ा देना चाहिए. चीन फिलहाल आर्थिक मोर्चे पर काफी जूझ रहा है और अमेरिका ने भी उसके खिलाफ व्यापार युद्ध शुरू किया हुआ है. इसे देखते हुए भारत के लिए ऐसा करना अपेक्षित है, ताकि चीन को यह पता चल सके कि किसी आतंकी को बचाने का नतीजा क्या होता है. यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को और मजबूती देगी.

मसूद को बचाने की चालें

हालिया दो दशकों में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है. इसे देखते हुए साल 2009, 2016, 2017 में भी कोशिश की गयी थी कि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया जाये और उस पर शिकंजा कसा जाये. लेकिन, हर बार चीन इस कोशिश पर पानी फेर देता है.

साल 2009: 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था. जिसके बाद मसूद अजहर की इस हमले में संलिप्तता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र में साल 2009 में प्रस्ताव लाया गया था कि अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाये. भारत को दुनियाभर से सहयोग मिला था और 13 देशों ने भरपूर समर्थन दिया था. लेकिन, चीन ने मसूद के खिलाफ सबूत दिखाने की बात करके प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का प्रयोग किया था.

साल 2016: मसूद अजहर पर वैश्विक आतंकी घोषित कर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव साल 2016 में भी आया था. जनवरी, 2016 में पठानकोट वायुसेना हवाई अड्डे पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसका मास्टरमाइंड मसूद अजहर था. संयुक्त राष्ट्र में मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया, जिसे 14 देशों के वोट भी मिले, लेकिन चीन ने एक बार फिर सबूत दिखाने की रट लगाकर मार्च और अक्तूबर, 2016 में दो बार इस प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा दी.

साल 2017: सितंबर, 2016 में उरी में सेना के जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 19 जवानों की जान चली गयी थी. इस हमले का मास्टरमाइंड भी मसूद अजहर ही था. जिसके बाद, साल 2017 में पी-3 देश अजहर मसूद के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आये थे और पी-3 देशों के इस प्रस्ताव का समर्थन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने खुलकर किया था. लेकिन, एक बार फिर प्रस्ताव पर सबूत के अभाव व आम सहमति न बनने का बहाना देकर चीन ने विरोध किया और मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित होने से रोक दिया.

साल 2019: पिछले माह 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर फिदायीन हमला हुआ, जिसमें देश के 40 से अधिक जवान शहीद हो गये थे. इस भयानक आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी, जिसका सरगना आतंकी मसूद अजहर है. पुलवामा हमले के बाद दुनिया के सभी प्रमुख देश भारत के समर्थन में आये और हर संभव मदद की पेशकश भी की. इसके बाद, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस आगे बढ़कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में प्रस्ताव ले आये कि अब मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया जाये और प्रतिबंधित कर दिया जाये. इस प्रस्ताव पर विचार करने व आपत्ति दर्ज कराने के लिए 10 दिन का समय भी दिया था, लेकिन प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 10 दिन के समय को कम बताकर चीन ने प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा दी.

चीनी उत्पादों के बहिष्कार का होगा दूरगामी असर

संयुक्त राष्ट्र में जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी ठहराये जाने पर चीन द्वारा अड़ंगा लगाये जाने से भारत में गुस्सा है. इसी कारण इन दिनों ट्विटर पर चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान भी किया जा रहा है. यहां यह जानना महत्वपूर्ण है कि चीनी उत्पादों के बहिष्कार का हमारे देश पर कैसा असर पड़ेगा. अगर हम चीनी उत्पाद का बहिष्कार करते हैं तो हमारे पास कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल व केमिकल गुड्स के साथ ही इंटरमीडिएट व कंज्यूमर गुड्स की कमी हो जायेगी, जिससे हमारे उद्योग प्रभावित होंगे. चीन से निर्यात होनेवाले ये उत्पाद हमारे कई प्रमुख उद्योगों के लिए बहुत ही जरूरी हैं. दूसरा, चीनी सामान सस्ते होते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा उन्हें कई तरह की रियायतें दी जाती हैं. ऐसे में इनके बहिष्कार से उत्पादों की लागत बढ़ जायेगी. नतीजा, हमें उन्हें खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. इतना ही नहीं ऊर्जा, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है. बीते वर्ष लोकसभा में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बताया था कि पिछले तीन वर्षों से भारत ने अपनी सौर उपकरणों की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा चीन से आयात किया है. आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2017-18 में भारत ने तकरीबन साढ़े तीन बिलियन डॉलर के सौर उपकरण चीन से आयात किये थे. इसके अलावा, वर्ष 2018-19 में चीन ने 80 प्रतिशत से अधिक एंटीबायोटिक्स और 60 प्रतिशत से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद व उसके घटक भारत को निर्यात किये थे. इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय उद्योग के कुछ प्रमुख क्षेत्र चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, जबकि चीन के साथ ऐसा नहीं है. लेकिन एक सच यह भी है कि भले ही आज भारत द्वारा चीन में निर्यात किये जाने का प्रतिशत कम है, लेकिन आगे चलकर यह चीन को प्रभावित करेगा. ऐसे में यदि हमारे यहां चीनी उत्पादों का बहिष्कार होता है तो इसका प्रभाव चीन पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है, लेकिन फिलहाल इस प्रभाव की तीव्रता चीन की बजाय भारत को ज्यादा महसूस होगी.

वैश्विक आतंकी घोषित करने की प्रक्रिया

किसी भी व्यक्ति को वैश्विक आतंकी घोषित करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद करती है. इसमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस स्थाई सदस्य हैं और दस अस्थाई सदस्य होते हैं. वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों में से कोई भी इसका प्रस्ताव ला सकता है. इसके बाद बाकी सदस्य देश इस पर अपना मत रखते हैं. ऐसे प्रस्ताव पर पांचों स्थाई सदस्यों का सहमत होना जरूरी है. परिषद के स्थाई सदस्यों के पास वीटो पावर यानी प्रस्ताव से असहमत होने का अधिकार होता है. प्रस्ताव आने के बाद 10 दिनों (कार्य दिवसों) तक इस पर आपत्तियां मांगी जाती हैं. अगर कोई स्थाई सदस्य इस अवधि में आपत्ति दर्ज नहीं करवाता तो प्रस्ताव पास हो जाता है. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति प्रस्ताव 1267 सूची में उस व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाता है और वह वैश्विक आतंकी घोषित हो जाता है. लेकिन यदि किसी सदस्य ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जता दी यानी वीटो कर दिया तो यह प्रस्ताव पास नहीं होता. आपत्ति जताये जाने के बाद यह प्रस्ताव कम से कम छह महीने के लिए रुक जाता है. यह आपत्ति तीन महीने और बढ़ाई जा सकती है. इसके बाद फिर से इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है.

क्या है दंड विधान?

- जब किसी व्यक्ति को वैश्विक आतंकी घोषित किया जाता है तो उसकी संपत्ति जिस देश में होती है, वह देश उसे तुरंत जब्त कर लेता है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि वैश्विक आतंकी घोषित किये गये व्यक्ति को कहीं से किसी तरह की वित्तीय मदद न मिलने पाये.
- ऐसे व्यक्ति को किसी भी देश में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती है. इतना ही नहीं, वह व्यक्ति जिस देश में होगा वहां भी उसे किसी तरह की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.
- कोई भी देश ऐसे व्यक्ति को हथियार, हथियार बनाने में काम आने वाले सामान और तकनीकी सहायता मुहैया नहीं करा सकता है

निंदनीय है चीन का रवैया

शशांक
पूर्व विदेश सचिव

मसूद अजहर के आतंकवादी सरगना होने का चीन पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है. ऐसा नहीं है कि चीन आतंकवाद के खिलाफ नहीं है, हालांकि उसने ऐसे फैसले लिए हैं जिससे भारत हीं नहीं, पूरे विश्व के मन में उसके खिलाफ ऐसी धारणा बन जाती है कि वह आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है. ऐसी स्थिति में साफ लगता है कि पाकिस्तान ही चीन के ऊपर दबाव डाल रहा है. चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे अधिक फायदा पाकिस्तान की सेना, उनके हुक्मरानों और पंजाब क्षेत्र को होनेवाला है, वहीं चीन के लिए सामरिक दृष्टि से यह परियोजना महत्वपूर्ण है. इसलिए, पाकिस्तान की सेना व हुक्मरान चीन के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब होते हैं और मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित नहीं होने. पाकिस्तान चीन को बार-बार कहता है कि सारी परियोजनाओं के लिए यह बहुत जरूरी है कि चीन पाकिस्तान के खिलाफ न जाये. चीन ने खुद को ऐसी स्थिति में फंसा लिया है. हमने अमेरिका, यूरोपीय संघ के मामले में भी देखा है कि जब इनके रिश्ते पाकिस्तान के साथ अच्छे थे, तब पाकिस्तान इन्हें भी तरह-तरह के दबाव में लाता था और अपने खिलाफ वोट नहीं होने देता था. पाकिस्तान अपनी स्थिति का हमेशा फायदा उठाता रहा है. पाकिस्तान के लिए इस समय भारत में आतंकवाद फैलाना प्राथमिकता बनी हुई है. सारे देश मना कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं मानता. चूंकि, चीन उसके कब्जे में है, इसका वह फायदा उठाता है. चीन की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं. चीन अगले 20 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने का सपना देख रहा है. 'वन बेल्ट वन रोड' के बाद अब 'चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर' चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, जिससे चीन को तेल के संसाधन मिलने में आसानी होगी, बाकायदा कॉलोनी बसायी जा रही है जिससे चीन खाड़ी देशों के बहुत करीब हो जायेगा. इसलिए, पाकिस्तान को साथ रखना चीन के लिए बहुत आवश्यक है. जहां तक आतंकवाद की बात है, चीन खुद ही आतंकवाद से पीड़ित है. पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के अलावा भी अलकायदा जैसे जितने आतंकी संगठन हैं, उनसे चीन न चाहते हुए भी संबंध बनाकर रखना चाहता है, जिससे वे चीन को तंग न करने लग जायें. ये संगठन कहीं और आतंकवाद फैला रहे हैं, तो चीन इनकी मदद करने को भी तैयार है. यह बहुत कुटिल और निंदनीय रवैया है कि चीन अपने देश में आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन कहीं और आतंक फैले तो उसे कोई परवाह नहीं होती है और आतंकवादियों को बचा लेता है.

भारत के अंदर चीन के खिलाफ अभियान छिड़ा हुआ है. लेकिन, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आनेवाले 15-20 सालों में हमें भी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में उभरकर आना है. चीन के साथ भी हमें दो तरह के रिश्ते निभाने पड़ेंगे. हमें कुछ मामलों में उनका सहयोग करना पड़ेगा, वहीं कुछ में प्रतिस्पर्धा में शामिल होना पड़ेगा और खिलाफ जाना पड़ेगा. हम यह पूरी तरह से मानकर नहीं चल सकते कि चीन हमारा दुश्मन है और उसे सबक सिखाना है. हालांकि, देश में सबक सिखाने की यह भावना घर कर गयी है. लेकिन, हमें अपने आपको संभालना होगा. पाकिस्तान आतंक फैलाकर निरंतर यही कोशिश कर रहा है कि भारत अपने रास्ते से भटक जाये और चीन भी उसे नहीं रोकता कि भारत धीमी चाल से बढ़ेगा तो चीन अव्वल बना रहेगा. इसलिए, भारत को प्रगति के रास्ते से हटना नहीं चाहिए और इसी के अनुसार दूरगामी नीतियों को साथ लेकर चलना चाहिए. हमारी वैश्विक साख बढ़ती देखकर चीन में खलबली मच जाती है. हमें इसी नीति को आगे बढ़ाना चाहिए और दुनिया की अन्य शक्तियों के साथ संबंध मजबूत करते रहना चाहिए.